उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) कागज उत्पादन संयन्त्रों की स्थापना करने के लिए जिनमें प्रत्येक की क्षमता 10,000 मी० टन प्रतिवर्ष या इससे कम है, 1975 के अन्त तक 24 पार्टियों को 1,58,700 मी० टन क्षमता के औद्योगिक लाइसेंस और आशयपत्र मंजूर किए गए हैं। उनमें से अधिकतर योजनायें कृषीय अवशेषों और देशी संयन्त्रों व मशीनों पर आधारित है। हां, कुछ एकक पुरानी आयातित मशीनों पर आधारित हैं।

सहकारी सूत मिलें

2775. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी सूत मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) अलाभकारी सहकारी कताई मिलों की अपनी संस्थापित क्षमता न्यूनतम 25000 तकलों तक बढा कर स्वयं को आत्म-निर्भर बनाने में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहायता देने की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना चलाई जा रही है। वर्ष 1974-75 और 1975-76 में राज्य सरकारों को सहकारी कताई मिलों की अंशपूंजी में अंश दान देने के लिए 249.60 लाख रु० की सहायता दी गई, ताकि ये मिलें अपनी संस्थापित क्षमता को बढ़ा सकें।

वस्त्र उद्योग में आये संकट के कारण सहकारी कताई मिलों को वर्ष 1974-75 में और 1975-76 में भी नकदी के रूप में भारी हानि हुई। इन सहकारी सोसायटियों के पास बैंकों से कार्यकर पूंजी ऋण लेने के लिए आवश्यक उपान्त (मार्जिन) धन की व्यवस्था हेतु पर्याप्त नकद संसाधन हो सकें, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी कताई मिलों की सहायता देने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत निगम ने अब तक तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 20 सहकारी कताई मिलों की सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को 147.385 लाख रु० की ऋण-सहायता मंजूर की है।

मध्य प्रदेश में विद्युत् का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सहायता

2776. श्री गंगा चरण दीक्षित क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्युत् की कमी दूर करने की दृष्टि से 1000 से 1500 मैगावाट की तापीय विद्युत् परियोजना कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से तत्काल सहायता करने का अनुरोध किया है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1000 से 1500 मैगावाट की क्षमता वाले ताप-विद्युत् केन्द्र

की स्थापना के लिए कोई परियोजना मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Loans to small and middle-sized industries

2777. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government propose to give financial assistance to small and middle-sized industries by way of interest-free loans;

(b) if so, the maximum amount of loan for such projects;

(c) the names of the agencies through which such loans are likely to be distributed; and

(d) the criteria adopted by Government for the grant of such loans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Industrial Finance Corporation to finance Enterprises launched by Ex-Servicemen

2778. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the proposal to start an Industrial Finance Corporation to finance the new enterprises proposed to be launched by the ex-servicemen has made any headway; and

(b) if so, the progress made in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK): (a) and (b) The proposal to set up a Public Sector Corporation to help ex-servicemen to set up new industrial enterprises has been given up. It has, however, been decided that this work should be organised by the Government itself departmentally. The question of establishing suitable organisation for this purpose in a few industrial cities where there are large concentrations of ex-servicemen is at present under consideration in consultation with some State Governments.

Cement Factory in Bilaspur

2779. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply given on the 21st January, 1976 to the Unstarred Question No. 920 regarding Cement Factory in Bilaspur, Himachal Pradesh and state the progress made in the setting up of the Cement Factory?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): A letter of intent No. LI: 87(76) dated 18-3-1976 has since been issued to M/s. Associated Cement Companies Limited, Bombay, for the establishment of a new undertaking in District Bilaspur, Himachal Pradesh, for the manufacture of 4 lakh tonnes per annum of Portland Cement.

Sample Survey by National Sample Survey Organisation

2780. PROF NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the National Sample Survey Organisation has any units co-terminous with the States for the purpose of effective sample survey; and